



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 1999/ज्येष्ठ 13, 1921
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 1999/JYAISTHA 13, 1921

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक मामले विभाग)
बीमा खंड
(अधिसूचना)

नई दिल्ली, 3 जून, 1999

का. आ. 415 (अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971 के नियम 6 के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित राजपत्रित अधिकारी को उस सम्पदा अधिकारी के समक्ष लंबित स्थानान्तरण की कार्यवाहियों की सुनवाई के लिए और उक्त सारणी के स्तंभ (2) के सामने विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में, किसी अन्य सम्पदा अधिकारी को जो ऐसे निपटान के लिए सक्षम हो, निपटान के लिए प्राधिकृत करती है।

तालिका

राजपत्रित अधिकारी	सरकारी स्थान
(1)	(2)
श्री आर. रंगनाथ, निदेशक, आर्थिक मामले विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार	भारतीय जीवन बीमा निगम के दिल्ली में स्वामित्व के स्थान।

[फा. सं. 138(1)आई एन एस-IV/99]
सी. एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के नियम 6 के अन्तर्गत सम्बद्ध मंत्रालय अर्थात् वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी स्थान अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी किया जाना है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(INSURANCE DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1999

S.O. 415 (E).—In pursuance of rule 6 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1971, the Central Government hereby authorises the gazetted officer mentioned in column (1) of the Table below to hear application for transfer of proceedings pending before an Estate Officer and pertaining to public premises specified against him in column (2) of the said Table for disposal to any other Estate Officer competent to dispose of the same.

TABLE

Gazetted Officer	Public Premises
(1)	(2)
Shri R. Renganath, Director, Department of Economic Affairs Ministry of Finance Government of India	Premises owned by Life Insurance Corporation of India in Delhi.

[F. No. 138(1)/Ins. IV/99]
C. S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

As per the provisions of rule 6 of Public Premises Act, 1971 an order has to be made under Public Premises Act by the Ministry concerned i.e. Ministry of Finance.

